भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

27.11.2019 के

अतारांकित प्रश्न सं. 1507 का उत्तर

तेलंगाना में लंबित रेलवे परियोजनाएं

1507. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डीः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण तेलंगाना राज्य में रेलवे परियोजनाएं लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त के लिए निधि कब तक जारी की जाएगी;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा हिस्सा जारी नहीं करने या निधि नहीं देने के कारण तेलंगाना राज्य में रेलवे परियोजनाएं लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्य सरकार से शीघ्र निधि जारी करने के संबंध में कोई आश्वासन मिला है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (च): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

तेलंगाना में लंबित रेलवे परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 27.11.2019 को लोक सभा में श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी के अतारांकित प्रश्न सं. 1507 के भाग (क) से (च) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) और (ख): जी नहीं। 20226 करोड़ रु. की लागत से 1604 किमी लंबाई वाली 13 परियोजनाएं जो तेलंगाना में पूर्णतः/अंशतः पड़ती हैं, नियोजन/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

उपर्युक्त 13 परियोजनाओं में से:

14816 करोड़ रु. की लागत से 1067 किमी लंबाई वाली 9 नई लाइन परियोजनाओं में से, 85 किमी लंबाई को चालू कर दिया गया है और मार्च 2019 तक, 2212 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इन परियोजनाओं का थ्रोफॉर्वर्ड 12603 करोड़ रु. है और 2019-20 के लिए 901 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है।

4 दोहरीकरण परियोजनाओं की लंबाई 537 किमी और लागत 5410 करोड़ रु. है। मार्च 2019 तक, 824 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इन परियोजनाओं का थ्रोफॉर्वर्ड 4586 करोड़ रु. है और 2019-20 के लिए 665 करोड़ रु. का परिव्यय प्रदान किया गया है।

(ग) से (च): जी हां। तेलंगाना राज्य में 13 परियोजनाओं में से, 3 परियोजनाएं तेलंगाना राज्य सरकार के साथ लागत साझाकरण आधार पर हैं और 01 परियोजना मैसर्स सिंगारेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड (मैसर्स एससीसीएल) के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर है। राज्य सरकार/मैसर्स एससीसीएल द्वारा धन के भुगतान में देरी करने/भुगतान न करने के कारण इन परियोजनाओं की प्रगति प्रभावित हो रही है। ऐसी परियोजनाओं के नाम निम्न प्रकार हैं:

1. **मनोहराबाद-कोठापल्ली (151.36 किमी) नई लाइन परियोजना**
2. **अक्कानापेट-मेडक (17.2 किमी) नई लाइन परियोजना**
3. **भद्राचलम-सत्तूपल्ली (56.25 किमी) नई लाइन (मैसर्स एससीसीएल द्वारा धन उपलब्ध कराया जाएगा)**

विवरण निम्नानुसार है:

(i) **<u>मनोहराबाद-कोठापल्ली (151.36 किमी) नई लाइन परियोजना:</u> राज्य सरकार को अपने हिस्से के रुप में 307 करोड़ रु. देने हैं, जिसकी तुलना में, अभी तक, केवल 60 करोड़ रु. जमा किए गए हैं। आज तक के व्यय के आधार पर, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा अभी 71.61 करोड़ रु. जमा कराए जाने शेष हैं। राज्य सरकार द्वारा धन का भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप बिलों का भुगतान नहीं हुआ जिससे कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है।**

(ii) **<u>अक्कानापेट-मेडक (17.2 किमी) नई लाइन परियोजना:</u> राज्य सरकार को 105.38 करोड़ रु. देने हैं, जिसके लिए अभी तक केवल 21.15 करोड़ रु. जमा किए गए हैं। आज तक के व्यय के आधार पर, तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा**

अभी 50.41 करोड़ रु. जमा कराए जाने शेष हैं। राज्य सरकार द्वारा धन का भुगतान न किए जाने के परिणामस्वरूप बिलों का भुगतान नहीं हुआ जिससे कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है।

(iii) <u>भद्राचलम-सत्तूपल्ली नई लाइन (56.25 किमी)</u>: यह रेल मंत्रालय और मैसर्स सिंगारेनी कोलियरीज़ कंपनी लिमिटेड के बीच एक लागत साझाकरण परियोजना है जिसकी शर्त यह है कि भूमि की लागत रेलवे द्वारा तथा निर्माण कार्य की लागत मैसर्स एससीसीएल द्वारा वहन की जाएगी। अभी तक 619 करोड़ रु. के स्वीकृत हिस्से में से, मैसर्स एससीसीएल द्वारा केवल 156.38 करोड़ रु. जमा किए गए हैं। अतः, स्वीकृत लागत के आधार पर, मैसर्स एससीसीएल द्वारा अभी 463 करोड़ रु. जमा कराए जाने शेष हैं। बहरहाल, अब परियोजना की लागत को संशोधित करके 952 करोड़ रु. कर दिया गया है, संशोधित लागत की स्वीकृति व बकाया राशि का भुगतान मैसर्स एससीसीएल से प्रतीक्षित है। मैसर्स एससीसीएल द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण परियोजना की प्रगति बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

अब तक, तेलंगाना सरकार ने रेलों को अपनी बकाया राशि का भुगतान करने की दिशा में कोई आश्वासन नहीं दिया है।

****